

उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

बनाम

सी. ओ. डी. चेओकी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड और

अन्य

17 जनवरी, 1997

[के. रामास्वामी और एस. सगीर अहमद, न्यायाधिपतिगण]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965/उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ नियम, 1968:

धारा 4,130 (2) (xii) और (xii-A)/नियम 393 (1) और (2) 393-A, 393-B, उप-नियम (4) का खंड (d), 440 (6) से (8) 444-A और 453 -प्रबंधन कमिटी -कमजोर वर्गों के पक्ष में आरक्षण-उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया -अपील पर, अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम और नियमों के प्रावधान संविधान की नीति और उद्देश्य के अनुरूप हैं -इसलिए, उच्च न्यायालय प्रावधानों को भारत के संविधान, कला के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करने में पूरी तरह से गलत था। 15, 19 (1) (ग), 29 और 46।

दमन सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [1985] 2 एससीसी 640;

बाबाजी कौंडाजी गराड आदि बनाम नासिक मर्चेट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक और अन्य , [1984] 2 एस. सी. सी. 50; तोगुरु सुधाकर रेड्डी व अन्य बनाम ए. पी. सरकार व अन्य, [1993] सप. (4) एस. सी. सी. 439; दमयंती नारंगा बनाम भारत संघ और अन्य , [1971] 3 एस. सी. आर. 840 और आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन विभाग के ललित नारायण मिश्रा, पटना आदि बनाम बिहार राज्य और अन्य, ए. आई. आर. (1988) एस. सी. 1136 पर भरोसा किया गया।

हे बनाम पर्थ के लॉर्ड प्रोवोस्ट, [1863] 4 मक्क एचएल (एससी) 535,544 और रे बेथलेम अस्पताल, (1875) एलआर 19 ईक्यू; 457, उद्धृत।

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 603-04 / 1997

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के C.M.W.P संख्या 40006 और 40121 / 1994 के 10.3.95 दिनांकित निर्णय और आदेश से

अपीलार्थीगण के लिए योगेश्वर प्रसाद, पी. के. बजाज और ए. के. श्रीवास्तव

प्रत्यर्थिगण के लिए राजू रामचंद्रन, एस. मार्कण्डेय, अजय सिंह, सुश्री सी. मार्कण्डेय, सुश्री मीनाक्षी अग्रवाल, प्रशांत कुमार, सुनील अंबवानी, सुश्री सुमन बाला रस्तोगी, एस. सी. पटेल और सुश्री रानी छाबड़ा

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

पक्षकार बनाया और हस्तक्षेप की अनुमति दी।

अनुमति दी गयी।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

ये अपीलें कानून की वैधता से संबंधित एक दिलचस्प प्रश्न उठाती हैं और यू. पी. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (संक्षेप में 'अधिनियम') और यू. पी. सहकारी समिति नियम, 1968 (संक्षेप में 'नियम') के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण या नामांकन प्रदान करने वाले अधिनियम और नियमों की वैधता, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

सवाल यह है: क्या यू. पी. विधानमंडल के पास बनाने की शक्ति है अधिनियम और नियमों में इस प्रकार संशोधन करने के लिए कानून जिसमें कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो? उच्च न्यायालय ने जहां तक कमजोर वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण, नियम 444-ए के उप-नियम (3) और नियम 453 के उप-नियम (5) के खंड (i) से संबंधित है,

धारा 130 (2) (xii) और (xii-A) और नियम 393 के उप-नियम (1) और (2), नियम 393-ए, नियम 393-बी, उप-नियम (4) के खंड (डी) और नियम 440 के उप-नियम (6) से (8) के प्रावधानों और स्पष्टीकरण को संविधान के अधिकार से बाहर घोषित किया और तदनुसार उन्हें रद्द कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 मार्च, 1995 के इस निर्णय पर सी. एम. डब्ल्यू. पी. सं. 40006 और 40121 / 1994, ये अपीलें दायर की जाने लगी हैं।

सहकारी समितियों के प्रबंधन में लोकतांत्रिक चरित्र के प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण समाज के सामान्य निकाय द्वारा चुनाव के आधार पर कमजोर वर्गों के सदस्यों, अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों को जगह नहीं मिलती है। नतीजतन, सरकार ने संशोधन पेश किया। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1994 ने अन्य पिछड़े वर्गों को कमजोर वर्गों के दायरे में लाया गया और उन सभी को सहकारी समिति की प्रबंधन समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत का सदस्य बनाया गया। ताकि वे सदस्यों के रूप में निर्वाचित या नामित हो सकें। अधिनियम की धारा 4 सहकारी समितियों के गठन का विवरण के मामले में दिशानिर्देश निर्धारित करती है और वह निम्नानुसार पढ़े जा सकते हैं:

"4. पंजीकृत होने वाली सोसायटी - इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, एक सोसायटी जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हित को बढ़ावा देना है या सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित एक सोसायटी है। ऐसी सोसायटी के संचालन को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।

व्याख्या- सहकारी सिद्धांत लागू होंगे।

(क) सदस्यों के आर्थिक हित में सहमति से प्रगति सार्वजनिक नैतिकता, शालीनता और राज्य नीति के प्रासंगिक निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति;

(ख) लाभ सूचना का विनियमन और प्रतिबंध;

(ग) मितव्ययिता, पारस्परिक सहायता और स्व-सहायता को बढ़ावा देना।

(घ) स्वैच्छिक सदस्यता; तथा

(ङ) समाज का लोकतांत्रिक संविधान।

अधिनियम की धारा 29 में प्रबंधन समिति के गठन की परिकल्पना की गई है, उप-धारा (1) निम्नानुसार है:

" 29 (1) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबंधन इस अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसार गठित प्रबंधन समिति में निहित होगा , जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो इसके द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं या लगाए जा सकते हैं। अधिनियम, नियम और उपनियम।' (जोर दिया गया)

अन्य उप-खंड प्रासंगिक नहीं हैं; इसलिए हटा दिए गए हैं। धारा 30 (1) से (4) सोसायटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित। धारा 130 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार नियम बना सकती है। उप-धारा (2) बताती है कि, विशेष रूप से, और उप-धारा (1) के तहत शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के तहत बनाए जाने वाले नियम इसमें उल्लिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं। इसके अनुसरण में, नियमों में संशोधन किया गया। खंड (xii) और (xii) A निम्नानुसार है:

"(xii) सहकारी समिति की प्रबंधन समिति के सदस्यों और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों

का परिसीमन, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण, चुनाव विवादों का निपटारा शामिल है, और ऐसे किसी भी मामले के संबंध में शुल्क का उद्ग्रहण;

(xii-ए) सहकारी समिति की प्रबंधन समिति में महिलाओं और कमजोर वर्गों के सदस्यों का नामांकन। "

ये संशोधन संशोधन अधिनियम 17-नियम 393 (1) द्वारा कानून पर लाए गए थे जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

"धारा 393(1) : एक सहकारी समिति की प्रबंधन समिति में उतने ही व्यक्ति हो सकते हैं जितने इसके उपनियमों में दिए जा सकते हैं, अधिकतम पंद्रह व्यक्तियों के अधीन। समिति की कोई अन्य समिति या उप-समिति इसकी प्रबंधन समिति से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी समिति या उप-समिति में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे ;

बशर्ते कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबंधन समिति में तीन सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए, एक पिछड़े वर्ग के

नागरिकों के लिए और एक महिलाओं के लिए आरक्षित होगी:-

बशर्ते कि उत्तर प्रदेश सहकारी निगम के मामले में उपभोक्ता फेडरेशन, केंद्रीय और प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों में तीन सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिनमें से दो महिलाओं के लिए और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम में "पिछड़ा वर्ग" पद है नागरिकों का" का वही अर्थ होगा जो जी के खंड (बी) में दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) की धारा 2 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) अधिनियम, 1994

(2)जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई सहकारी समिति किसी भी कारण से, प्रबंधन समिति में उतने व्यक्तियों को एकत्र करने में विफल रहती है जिनके लिए सीटें आरक्षित हैं यारिक्ति होने पर, कमी को पूरा किया जाएगा या दायर किया जाएगा , जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा ऐसी सोसायटी की प्रबंधन समिति में ऐसे वर्ग से संबंधित

व्यक्तियों को नामांकित करके। इन नियमों में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति "कमजोर वर्ग" का अर्थ उप-नियम (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्ति होगा।"

संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय और स्थिति और अवसर की समानता के साथ व्यक्ति की गरिमा प्रदान करती है। संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि "राज्य कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक हित को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देगा।" अधिनियम की धारा 4 का उद्देश्य सुविधाओं और अवसरों को प्रदान करके सहकारी सिद्धांतों द्वारा समाज के सदस्यों के आर्थिक सुधार को बढ़ाने के अवसर को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी सिद्धांतों के अनुसार समाज के सदस्यों के आर्थिक हित और स्थिति को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करता है। आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करना संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों में से एक है। इसलिए, धारा 4 का उद्देश्य धारा 4 के स्पष्टीकरण के खंड (ए) के संचालन द्वारा राज्य नीति की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों में प्रतिपादित सहकारी सिद्धांतों, नैतिकता, शालीनता और प्रासंगिक निर्देश सिद्धांतों और राज्य नीति के अनुसार संवैधानिक उद्देश्य को प्रभावी बनाना है। खंड (सी) के सभी वर्गों के

प्रतिनिधित्व की परिकल्पना की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज ताकि उन सभी को अधिनियम, नियमों या उप-कानूनों के तहत स्थापित और पंजीकृत समाज के सदस्य बनकर सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अवसर मिल सके। जब कमजोर वर्गों का समिति में नामांकन में कमी के कारण चुनावी प्रक्रिया द्वारा समिति के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसके प्रबंधन के लिए चुने जाने से यह अधिनियम के तहत प्रमुख कार्यक्रमों और नीति में से एक है। अनुच्छेद 366 का खंड 24 और (25) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति अधिसूचना प्रत्येक राज्य के लिए क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची निर्दिष्ट करने वाली की परिकल्पना की गई है। जहाँ तक महिलाओं का संबंध है, विनिर्देशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 में निर्दिष्ट वर्गों के रूप में की गई है। इस अधिनियम का अनुप्रयोग केवल अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से है और इससे अधिक नहीं। अधिनियम के तहत, समिति के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व का उद्देश्य. नियम चुनाव या नामांकन के लिए सिद्धांतों का प्रावधान करते हैं।

नियमों के नियम 393-ए और 393-बी निम्नानुसार हैं:

“इन नियमों या सोसायटी के उपनियमों में किसी बात के बावजूद , लेकिन नियम 453 के अधीन, यदि किसी सहकारी समिति की प्रबंधन समिति नियम 393 के उप-नियम (1) के परंतुक में संदर्भित है, इस नियम के प्रारंभ होने की तिथि पर उपरोक्त उपनियम में निर्दिष्ट कमजोर वर्गों या महिलाओं की संख्या में उतने व्यक्ति नहीं हैं, जितनी भी स्थिति हो, राज्य सरकार ऐसी समितियों की प्रबंधन समिति में नामांकन करेगी। नियम 393 के उप-नियम (1) के उक्त परंतुक में निर्दिष्ट सीमा तक कई व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना आवश्यक हो सकता है, और इस प्रकार नामांकन होने पर, संबंधित सोसायटी की प्रबंधन समिति आवश्यक संख्या में रजिस्ट्रार के प्राधिकार द्वारा लाटरी द्वारा व्यक्तियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, ताकि प्रबंधन समिति में ऐसे नामांकनों को समायोजित किया जा सके।

393-बी. जहां ऐसी सोसायटी की प्रबंधन समिति के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल में इतनी संख्या में व्यक्ति नहीं हैं, जैसा कि उपरोक्त नियमों में प्रावधानित है, वहां राज्य सरकार , ऐसी सोसायटी के उपनियमों में किसी बात के होते हुए भी, समिति में सदस्यों को नामांकित करेगी।

उसके प्रबंधन में उपरोक्त निर्दिष्ट नियम में निर्दिष्ट सीमा तक ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक संख्या में व्यक्ति होंगे और इस प्रकार नामांकन किए जाने पर, संबंधित सोसायटी की प्रबंधन समिति आवश्यक संख्या में व्यक्तियों को सेवानिवृत्त करेगी। ऐसे नामांकितों को समायोजित करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।"

440 उप-नियम (1) (4) (डी) निम्नानुसार है:

"(4) किसी सहकारी समिति के प्रबंधन समिति के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए, या किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के, जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार, इसमें किसी भी बात के बावजूद, सहकारी समिति या वर्ग के चुनाव के लिए नियम 441 के उप-नियम (2) के तहत नोटिस जारी करने से पहले, सोसायटी के उपनियम, जैसा भी मामला हो सहकारी समितियों की श्रेणी अनंतिम रूप से निर्धारित करती हैं-

(ए).....

(बी)

(सी).....

(डी) कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या।

नियम 444-ए (3) निम्नानुसार है:

"रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी, नियम 440 के उप-नियम (6) के प्रावधान के तहत, कमजोर वर्ग के लिए निर्वाचन क्षेत्रों/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण हिंदी वर्णमाला क्रम में रोटेशन द्वारा आरक्षित सीटों की सीमा तक किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों/क्षेत्रों के नाम जहां से प्रबंधन क्षेत्र समिति के सदस्य चुने जाने हैं।"

नियम 453(1)(एच) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सहकारी समिति की प्रबंधन समिति का सदस्य बनने या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उसकी सामान्य निकाय का सदस्य नहीं है।

ये नियम निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं और उनके रोटेशन का प्रावधान करते हैं कमजोर वर्गों के चुनाव के प्रावधानों के अभाव के बावजूद अनुभाग ताकि धारा 130(2)(xii) और (xii-a) के साथ पठित धारा 29(1) के उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके। इन प्रावधानों का एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण अध्ययन, इस प्रकार, स्पष्ट रूप से संकेत देगा कि प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबंधन जिसका उद्देश्य एफ अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप है, इसके अनुसार गठित प्रबंधन समिति में निहित किया जाएगा।

कमजोर वर्गों को शामिल करते हुए वैकल्पिक घटक के साथ अधिनियम, नियम और उपनियम। इसके अभाव में उनका नामांकन करके। धारा 130(2)(xii) और (xiii-ए) में कहा गया है कि बनाए जाने वाले नियमों में महिलाओं के लिए आरक्षण सहित सहकारी समिति के प्रबंधन समिति के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान हो सकता है। और अन्य पिछड़ा वर्ग। इसलिए, अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए नियम बनाए गए हैं, अर्थात् प्रबंधन समिति के चयन के लिए और चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जैसा कि अधिनियम और नियमों के तहत परिकल्पना की गई है, वे निर्वाचित होते हैं। यदि कमजोर वर्गों के सदस्य, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित एच जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएँ निर्वाचित नहीं होतीं, सरकार को कमजोर वर्गों से संबंधित सदस्यों और महिलाओं को तीन सीटों की सीमा तक नामांकित करने की शक्ति दी गई है, जैसा कि प्रत्येक कंपनी के ऑपरेटिव सोसायटी के प्रबंधन की प्रत्येक समिति में एक अनुसूचित जाति , एक पिछड़ा वर्ग और एक महिला है।

प्रश्न यह है: कि क्या ऐसी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) का उल्लंघन है? उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचन्द्रन का तर्क है कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को एक सोसायटी बनाने या उसका सदस्य बनने का अधिकार प्रदान किया है। सोसायटी के गठन में उपनियमों

के अनुसार सोसायटी के उद्देश्यों को पूरा करने वाले किसी भी सदस्य के चरित्र या नामांकन को शामिल करने की हिंसा शामिल है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। इसलिए, सामान्य निकाय का सदस्य बने बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में नहीं लाया या नामांकित किया जा सकता है। दमन सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [1985] 2 एससीसी 670 एट 681, में संविधान पीठ ने माना था कि सोसायटी का निर्माण, संविधान और प्रबंधन कानून का एक प्राणी है। वे कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं और इसलिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार के उल्लंघन के आधार पर उनकी संरचना में वैधानिक हस्तक्षेप पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। पैरा 11 में, इस न्यायालय ने माना कि एक बार जब कोई व्यक्ति सहकारी सोसायटी का सदस्य बन जाता है, तो वह सोसायटी के लिए अपना व्यक्तित्व खो देता है और कानून और उपनियमों द्वारा उसे दिए गए अधिकारों के अलावा उसके पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है। उसे समाज के माध्यम से कार्य करना और बोलना चाहिए या बल्कि, समाज अकेले ही उसके लिए कार्य कर सकता है और एक निकाय के रूप में समाज के अधिकारों या कर्तव्यों के बारे में बोल सकता है, सवाल यह है कि क्या विधायिका के पास सदस्यों के नामांकन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। सहकारी समितियों

की प्रबंधन समिति के चुनाव के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं पर इस न्यायालय ने बाबाजी कौंडाली गारद आदि बनाम नासिक मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक और मामले में विचार किया था। अन्य, [1984] 2 एससीसी 50। पैराग्राफ 9 और 12 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"अधिनियम 1960 में अधिनियमित किया गया था और इसने बॉम्बे सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1925 को निरस्त कर दिया था। धारा 73 अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसार गठित होने वाली एक समिति में प्रत्येक सोसायटी के प्रबंधन के उप कानून को निहित करने का प्रावधान करती है। अधिनियम के प्रारंभ में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और कमजोर वर्ग के पक्ष में सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण को अनिवार्य बनाने वाली धारा 73-बी को 1969 के अधिनियम 27 में संशोधन करके अधिनियम में शामिल किया गया था। यह विशिष्ट संशोधन क्यों किया गया था? अधिनियम की कार्यप्रणाली ने एक दुखद स्थिति का खुलासा किया होगा कि भले ही सहकारी आंदोलन का तेजी से विस्तार हो रहा था, लेकिन अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति या समाज के सदस्यों के कमजोर वर्ग के सदस्यों का समिति में प्रतिनिधित्व नहीं था और समाज की व्यापक नीतियों और प्रबंधन को निर्धारित करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अवसर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 43 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आर्थिक स्वतंत्रता की हमारी आगे की यात्रा में, भारत का एक सहकारी राष्ट्रमंडल बनना तय था। चूँकि गतिविधियाँ विविध थीं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के प्रति समर्पित व्यक्ति की प्रत्येक गतिविधि काफी हद तक सहकारी गतिविधियों से प्रभावित होती है, जैसे बीज वितरण, ऋण, कृषि उपज का निपटान आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं। सहकारी आंदोलन ने जो विशाल प्रगति की, उससे वे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे, वे सीधे और काफी हद तक इससे प्रभावित हुए। इससे बचने के लिए कि जो लोग अपने दैनिक जीवन में आंदोलन से प्रभावित होते हैं वे प्रबंधन परिषद और निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व करने

के अवसर से वंचित होकर द्वितीय श्रेणी का दर्जा प्राप्त करते हैं, धारा 73-बी जैसा प्रावधान लागू किया गया था। ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया जिन्हें आरक्षण के अभाव में उस समिति में चुना जाना मुश्किल हो सकता है जिसमें प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति निहित है। समाज के आदेशों के अधीनता के साथ प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति ऐसे व्यक्तियों को दासत्व में कम करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत होगी। एक सहकारी समिति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गई समिति द्वारा शासित किया जाना है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आरक्षित सीटों को भरने में शामिल किया जाना चाहिए अन्यथा समिति को प्रतिनिधि चरित्र का आनंद नहीं मिलेगा। कोई भी संविधान के भाग XVI और विशेष रूप से अनुच्छेद 330 और 332 में निहित प्रावधानों से प्रकाश डाल सकता है जो प्रदान करते हैं लोक सभा में और प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण और। उस समय की महसूस की गई आवश्यकताओं और वर्ग प्रभुत्व के ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने संवैधानिक व्यवस्था को जन्म

दिया। आरक्षण की गारंटी ताकि भारत वास्तव में संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन सके। एक गणराज्य पुरुष और संस्थान से बना है। यही कारण है कि चुनाव का प्रावधान करके और लोकतांत्रिक बनाने के लिए 'लोकतांत्रिक संस्थानों' की स्थापना करनी होगी। संस्थान वास्तव में प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के लिए सीटों का आरक्षण जो उनके पिछड़ेपन, शोषण और अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण सामाजिक और आर्थिक दोनों में प्रतिनिधित्व वर्ग प्रभुत्व का कारण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही आरक्षण की उत्पत्ति है। इसलिए, आरक्षण के लिए बनाए जाने वाले किसी भी प्रावधान में ऐसा निर्माण होना चाहिए जो आरक्षण बनाने वाले प्रावधान के मूल उद्देश्य और इरादे को आगे बढ़ाए और इसे विफल न करे। कानून में 'कानून की समानता' पर कार्यवाही कहा जाता है, उपचारात्मक का विस्तार करने के लिए निर्माण की एक विधि का उपयोग किया गया था हे बनाम लॉर्ड प्रोवोस्ट ऑफ़ पर्थ में, (1863) 4 मार्क। एचएल (एससी) 535, 544 लॉर्ड वेस्टबरी ने देखा कि निर्माण का तरीका जिसे 'कानून की इक्विटी' के रूप में जाना जाता है, "हमारे पहले के

क्रान्तियों के संबंध में बहुत सामान्य था, और उस सिद्धांत और तरीके से बहुत सुसंगत था जिसके अनुसार अधिनियम या उस समय संसद का गठन किया गया था"। निस्संदेह, आजकल निर्माण की यह विधा अनुपयोगी हो गई है। भले ही 'क्रान्तियों की समानता' की अभिव्यक्ति अप्रचलित हो गई है, फिर भी यह अभी भी कुछ हद तक उसी रूप में प्रचलन में है, यदि यह स्पष्ट है कि न्याय के सिद्धांतों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है जो कि किसी अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। संसद, न्याय की अदालत शब्दों के अलावा अधिनियम की भावना और अर्थ पर भी विचार करेगी। इस संदर्भ में, रे बेथेम अस्पताल में जेसल एम.आर. के शब्दों को याद किया जा सकता है, (1875) एलआर 19 ईक्यू ; 457, कि 'क्रान्तियों की समानता' का अर्थ यह भी हो सकता है कि "किसी अधिनियम को उसके इरादे के अनुसार समझना, हालांकि उसके शब्दों के अनुसार नहीं"। वैकल्पिक रूप से, इस न्यायालय द्वारा अक्सर देखे गए हेवडन के परीक्षण को लाया जा सकता है कि किसी क्रान्तियों के वास्तविक इरादे तक पहुंचने के लिए, न्यायालय को स्वयं से प्रश्न पूछने चाहिए: (1) इससे पहले निर्माणाधीन

प्रावधान की स्थिति क्या थी (2) प्रावधान शुरू करने से पहले क्या शरारत या दोष देखा जाता था, (3) क्या यह उपचारात्मक था और (4) उपचार का कारण। इस परीक्षण को लागू करने पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के सदस्यों के कमजोर वर्ग की स्थिति और दुर्दशा को देखते हुए भी वही परिणाम आएगा, हालांकि वे समाज के विच्छेद के अधीन होंगे, जिनके पास कोई नहीं था। प्रबंधकीय परिषदों में आवाज उठाने और ऐसे व्यक्तियों के कद और स्थिति को बढ़ाने के लिए ताकि उन्हें समाज के अन्य वर्गों के साथ समानता के स्तर पर लाया जा सके, आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसके अभाव में जिनके पक्ष में आरक्षण किया गया था, वे निर्णय लेने वाले निकायों के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते थे। धारा 73-बी पर लागू निर्माण के वास्तविक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इन पहलुओं को हमारे सामने शुरू करना चाहिए।

जब कानून के अनुसार किसी निश्चित चीज़ को एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो इसे केवल उसी तरीके से किया जा सकता है जब तक कि कानून में कोई विपरीत संकेत न पाया जाए। यदि

विधानमंडल 'यदि ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं चुना जाता है' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है तो यह निस्संदेह सुझाव देता है कि मुख्य रूप से आरक्षित सीटें चुनाव द्वारा भरी जानी हैं। चुनाव करने में असफल होने पर, कोई नियुक्ति या सह-विकल्प का सहारा ले सकता है। धारा 73-बी में निर्धारित पद्धति का कालानुक्रम जिसके द्वारा सीटें भरी जानी हैं, विधायी इरादे को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान चुनाव को दिया जाता है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एक प्रतिनिधि संस्था को आम तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाना चाहिए। इसलिए , यह धारा कहती है कि 'यदि ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता है' तो इसका मतलब यह होगा कि जिन अधिकारियों पर चुनाव कराने का कर्तव्य है, उन्हें चुनाव कराने की व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यदि यह जानकारी देते हुए चयन किया जाता है कि आरक्षित सीटें हैं और कोई भी उम्मीदवार आरक्षित सीटों के लिए चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो विधानमंडल ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि सीटें खाली नहीं रहेंगी, बल्कि नियुक्ति या सह-विकल्प जैसे दो सहायक

तरीकों से भरी जा सकती हैं। सहकारिता को वह चुनाव के बराबर नहीं रख सकता, जो सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीका है जिसके द्वारा प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। इसलिए, 73 - बी अनुभाग में नियोजित आरक्षित सीटों को भरने की पद्धति की भाषा और कालक्रम इसके सही निर्माण के लिए एक संकेत प्रदान करता है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि चुनाव द्वारा सीटें भरने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यह सीटों को भरने में चुनाव मशीनरी की विफलता है जो संबंधित प्राधिकारी को नियुक्ति या सह-विकल्प द्वारा सीटें भरने में सक्षम बनाती है। नियुक्ति या सह-विकल्प द्वारा आरक्षित सीटों को भरने की पूर्ववर्ती शर्त चुनाव आयोजित करना है और ऐसे व्यक्तियों को चुनने में विफलता आरक्षित सीटों को भरने के लिए अन्य तरीकों का सहारा लेने की अनुमति देगी।”

तोगुरु सुधाकर रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य, [1993] अनुपूरक 4 एससीसी 439 के मामले में, इस न्यायालय ने एपी सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 31 के तहत सहकारी समितियों में महिलाओं को नामांकित करने की सरकार की शक्ति पर विचार किया और

अधिनियम की वैधता और उनके नामांकन के लिए सरकार की शक्ति को बरकरार रखा गया।

इस प्रकार, यह स्थापित कानून है कि किसी भी नागरिक को सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। उसका अधिकार कानून के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। अतः समाज का सदस्य बनने या बने रहने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। सोसायटी का सदस्य बनने तथा सदस्य बनने हेतु निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने तथा प्रवेश पर वह सदस्य बन जाता है। उनका सोसायटी का सदस्य होना समय-समय पर लागू अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अधीन है। सोसायटी के एक सदस्य के पास सोसायटी के लिए कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और यह सोसायटी ही है जो कॉर्पोरेट समुच्चय के रूप में प्रतिनिधित्व करने की हकदार है। कोई भी व्यक्तिगत सदस्य अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के प्रावधानों की संवैधानिकता पर हमला करने का हकदार नहीं है क्योंकि अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के तहत उसका अधिकार है और वह इसके संचालन के अधीन है। धारा स्रोत से ऊपर नहीं उठ सकती।

इसलिए, गठित की गई सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अलावा व्यक्तिगत सदस्यों के पास समिति के प्रबंधन का कोई मौलिक

अधिकार नहीं है। समिति का प्रबंधन अधिनियम की धारा 29 द्वारा विनियमित है। इसकी संरचना भी अधिनियम द्वारा विनियमित होती है और इसे नियमों और उपनियमों के अनुसार होना चाहिए। यहां उल्लिखित नियम धारा 130 (2) (xii) और (xi-ए) में निहित प्रावधानों और चुनाव में आरक्षण प्रदान करने वाले नियमों को आगे बढ़ाने और कमजोर वर्गों और महिलाओं से संबंधित सदस्यों की एक समिति या प्रबंधन समिति में नामांकन के लिए संविधान की प्रस्तावना, अनुच्छेद 38 और 46 द्वारा सुनिश्चित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लागू अनुरूप होने चाहिए।।

श्री राजू रामचन्द्रन ने दमयंती नारंग बानाम भारत संघ एवं अन्य, [1971] 3 एससीआर 840 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, सरकार कानून बनाने की शक्ति वंचित है, जब तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (4) द्वारा नियंत्रित किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन न किया गया हो। सरकार के पास कमजोर वर्गों और महिलाओं के आरक्षण को शामिल करने वाला कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। हमें विवाद में कोई ताकत नहीं दिखती. यह देखा जा सकता है कि उसमें, सरकार ने प्रविष्टि 63, सूची I के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत साहित्य सम्मेलन अधिनियम बनाया

था। इस न्यायालय ने बताया कि अधिनियम में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि समिति का राष्ट्रीय महत्व है। इसलिए , यह माना कि संसद के पास सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी के संस्थापक सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध समाज को शामिल करने और बाहरी सदस्यों को शामिल करने वाला कानून बनाने की शक्ति का अभाव था। इस न्यायालय ने यह भी माना कि मूल सोसायटी से संबंधित संपत्तियाँ धारा 4 के तहत निगमित सोसायटी में निहित थीं बिना किसी मुआवजे के अधिनियम का ई. इसलिए, यह अनुच्छेद का उल्लंघन था भारत के संविधान का 31, जैसा कि तब था। उसमें मौजूद अनुपात का इस मामले में तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक सेवाओं पर लागू और कवर करने वाले राज्य लोक सेवा आरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित "अन्य पिछड़ा वर्ग" को समाज के सदस्यों के रूप में शामिल किया जा रहा है जो अन्यथा पात्र नहीं हैं और इसलिए, संशोधन द्वारा उन्हें शामिल किया जा रहा है। 15.7.1994 को बनाया गया नियम असंवैधानिक है। इसके समर्थन में, उनका तर्क है कि यद्यपि अधिनियम के अनुच्छेद 15 (4) में यह प्रावधान है कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 (2) और 29 (2) के अधीन है, लेकिन यह परिकल्पना नहीं करता है कि यह अनुच्छेद 19(के भी अधीन है) 1)(सी) का संविधान। इसलिए कमजोर वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक

है। हमें विवाद में कोई ताकत नहीं दिखती. अनुच्छेद 15(4) का उद्देश्य राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश या सहायता प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 15(2) और 29(2) में गारंटीकृत सामान्य समानता के निषेध को हटाना है। राज्य। इसलिए, उनका उद्देश्य अनुच्छेद एच 19(1)(सी) से अलग और अलग है। हालाँकि अनुच्छेद 19(1)(सी) संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित। जैसा कि इस न्यायालय ने माना है, एक बार जब कोई सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो जाती है, तो धारा 29 और उसके तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से सोसायटी का प्रबंधन विधिवत निर्वाचित सदस्यों द्वारा विनियमित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार, सभी पात्र व्यक्ति चुनाव लड़ने के हकदार हैं, कमजोर वर्ग के निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति में और निर्वाचित महिला सदस्यों का सरकार द्वारा नामांकन किया जाता है। आयन अधिनियम की नीतियों में से एक के रूप में परिकल्पित वैकल्पिक व्यवस्था है, इसलिए, न्यायालय नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) (सी) का उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है।

अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि आयोजित किया गया था, चुनाव लड़ना। कमजोर वर्गों से संबंधित निर्वाचित सदस्यों

और निर्वाचित महिला सदस्यों की अनुपस्थिति में सरकार द्वारा उनका नामांकन अधिनियम की नीतियों में से एक के रूप में परिकल्पित वैकल्पिक व्यवस्था है, इसलिए, न्यायालय नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) का असंवैधानिक उल्लंघन घोषित नहीं कर सकता है।

फिर यह तर्क दिया गया कि कमजोर वर्गों से संबंधित सदस्यों का नामांकन मनमाना और असंबद्ध है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह देखा गया है कि अधिनियम के प्रावधान और संबंधित नियम आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, व्यक्तियों की पहचान की जाती है। उपनियम उन सदस्यों की पात्रता निर्धारित करते हैं जो समाज के सदस्यों के रूप में नामांकित होने के पात्र होंगे और नियमों के नियम 393 के तहत अयोग्यताएं प्रदान की गई हैं। उन परिस्थितियों में, ये प्रावधान अधिनियम के तहत दिशानिर्देशों को दर्शाते हैं। यदि किसी को अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नामांकित किया जाता है, तो यह एक व्यक्तिगत मामला होगा जिस पर अलग से विचार किया जाएगा, लेकिन अकेले उस आधार पर, अधिनियम और नियमों को अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता है।

श्री राजू रामचंद्रन ने आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन, पटना आदि बनाम बिहार राज्य और अन्य के ललित नारायण मिश्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उनके तर्क के समर्थन में एआईआर (1988) एससी 1136। लेकिन उसकी मदद करना तो दूर, उसमें अनुपात भी इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है।

इसके बाद कुछ उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री एस. मार्कंडेय ने तर्क दिया कि वर्कर्स ऑर्डिनेंस को-ऑपरेटिव सोसाइटी में कमजोर वर्ग शामिल हैं और कमजोर वर्गों को नामांकन या महिलाओं द्वारा शामिल किया जाता है जो सोसायटी के सदस्य नहीं बनते हैं। असंवैधानिक, प्रबंधन समिति में कमजोर वर्गों का चुनाव या नामांकन अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। यदि किसी समाज में केवल वे खंड शामिल हैं और निर्वाचित प्रबंधन समिति में वे शामिल हैं, तो उस खंड के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकन का सवाल ही नहीं उठता समिति में निर्वाचित सदस्यों के होने से, आवश्यक रूप से सरकार के पास समिति की अधूरी सदस्यता को नामांकित करने की शक्ति है।

इस प्रकार विचार करने पर, हमारा विचार है कि अधिनियम और नियमों के प्रावधान संविधान की नीति और उद्देश्य के अनुरूप हैं और, इसलिए, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान को संविधान के दायरे से बाहर घोषित करना पूरी तरह से गलत था।

तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं। रिट याचिका खारिज कर दी गई है।
कोई व्यय अधिरोपित नहीं।

अपीलें स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।